विचार बिन्दु

अपराधी मन संदेह का अड्डा है। –शेक्सपीयर

दुरस्त शहरी प्रशासन नागरिकों का मौलिक अधिकार

ऑक्सफ़ोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2026 में भारतीय शहरों की कमज़ोरियां उजागर हुई हैं। यह कमजोरियां उन हालात पर ज़्यादा ध्यान देने की मांग करती हैं जो शहरों को उत्पादक और रहने लायक बनाते हैं। इन हालात में राजस्थान के शहरों की हालत तो और भी गई-बीती है। यह इंडेक्स शहरों को पांच श्रेणियों में आंकता है: आर्थिक, मानव संसाधन, जीवन की गुणवत्ता, वातावरण और गवर्नेंस। टूटे हुए फुटपाथ; खुली नालियां;खुदी हुई सड़कें; इधर-उधर बिखरा हुआ निर्माण का मलबा; काम वाली जगहों के आस-पास जमा होता कचरा; खतरनाक रास्ते; ट्रैफिक का तंग रास्तों से जबरदस्ती गुजरना; और सड़क पार करने के लिए मलबे के बीच से रास्ता बनाना जैसे बुरे हालात राजस्थान के शहरों की दु:ख भरी कहानी कहते हैं। शहरों के ऐसे नज़ारों के हम अभ्यस्त हो चले हैं। महीनों तक सड़कों और जल निकासी के ढांचों की मरम्मत के काम चलते रहते हैं। जयपुर के सिविल लाइन्स पर बन रहा रेल्वे ओवरब्रिज बरसों से बन रहा है और किसी को पता नहीं कब तक पूरा होगा राज्य का अकेला ऐसा निर्माण नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई जिम्मेवार अधिकारी इन कामों को देखता भी है। इन्हीं रास्तों से सारे कामों के जिम्मेवार अधिकारी ही नहीं शासन और प्रशासन के प्रमुख लोग भी गुजरते हैं। व्यवस्थित प्लानिंग या समय पर काम पूरा कराने के लिये बीच-बीच में अदालतें जरूर निर्देश देती रहती हैं, लेकिन काम में गति आने या उसके बेहतर होने के कोई खास सबूत जमीनी हक़ीक़त में दिखाई नहीं देते हैं। मसला यह नहीं है कि शहरी ढांचे को मरम्मत या रखरखाव की ज़रूरत है। मसला यह है कि यह काम कैसे किया जाता है। सड़कों को खोदकर हफ़्तों और महीनों तक खुला क्यों छोड़ दिया जाता है? नालियों को खुला क्यों छोड़ दिया जाता है? पैदल चलने वालों को इंसान क्यों नहीं समझा जाता है? मलबे को सार्वजनिक ज़मीन पर क्यों पड़ा रहने दिया जाता है? ट्रैफिक डायवर्जन का मैनेजमेंट इतना खराब क्यों होता है? काम के क्रम, तालमेल या जवाबदेही का कोई स्पष्ट एहसास प्रशासन को क्यों नहीं होता? ऐसे सवाल मीडिया पर भी आते रहते हैं, लेकिन शासन-प्रशासन के कर्ता-धर्ता लोगों की नींद नहीं खुलती। शहरों की ये मुश्किलें गवर्नेंस की समस्याएं हैं। भारत के शहरी संकट पर जब बातें होती है तो उनमें अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की चर्चा होती है, लेकिन हर तरफ जो नज़र आता है वह ज़्यादा बुनियादी चीज़ है। वह है नागरिक प्रबंधन की कमी। हम फ्लाईओवर, मेट्रो लाइन और टेक्नोलॉजी पार्क बनाते हैं, फिर भी फुटपाथ का रखरखाव करने में असफल रहते हैं। यहां तक कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को बीच में पड़ कर चिन्हित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करना पड़ा है। हम विकसित देश बनने की बात करते हैं, फिर भी ऐसी अव्यवस्थित सार्वजनिक जगहों को बर्दाश्त करते हैं। इन हालात पर बाहरी लोगों की टिप्पणियां हमें चुभती हुई लगती हैं। सड़कों पर टूटे हुए कंक्रीट, खड्डों और बेतरतीब ट्रैफिक के बीच खड़े होकर, कोई भी इस आलोचना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता।कड़वा सच यहहै कि हमारे शहर अक्सर सिस्टम की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम के बावजूद काम करते हैं।

सच पूछो तो हम जिन मुश्किलों का सामना करते हैं उसके समाधान के लिये न तो किसी प्रकार की क्रांति की जरूरत है और न ही बहुत महंगे उपायों की। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तालमेल हो, उन्हें तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाय; फुटपाथ लगातार सुरक्षित और आसानी से इस्तेमाल करने लायक हों; रिहायशी इलाकों को बाज़ार बनने से रोका जाए तथा उनकी सड़कों को बेकाबू ट्रैफिक कॉरिडोर बनने से बचाया जाय; ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जाय; निर्माण के कचरे को तुरंत हटाया जाय; और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के खराब होने के बाद मरम्मत करने की बजाय, उसके खराब होने से पहले उसका ठीक से रखरखाव किया जाय जैसी सामान्य चीजें ही सारी समस्याएं हल कर सकती हैं। यह स्वीकार करना होगा कि समय के साथ शहर बदलेंगे ही। विकास तो होगा ही। लेकिन बिना प्लानिंग के विकास से अव्यवस्था फैलती है और नागरिक अनुशासन के बिना विकास से कामकाज में गड़बड़ी आती है। किसी शहर को सिर्फ़ उसकी रियल एस्टेट की कीमत, स्टार्टअप्स की संख्या या टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरक्की से नहीं मापा जासकता है। उसे इस बात से मापा जाना चाहिए कि वह अपने निवासियों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसी सुविधाएं देता है। जिस चीज़ की यहां सबसे अधिक कमी है, वह है व्यवस्थित नागरिक प्रबंधन की, जो शहरी विकास को उचित तरीके से नहीं होने को बाधित करता है। शहर केवल ईंट, पत्थर और कंक्रीट के ढांचे नहीं होते हैं, बल्कि वे आर्थिक अवसरों, नवाचार और सामाजिक गतिशीलता के जीवंत केंद्र होते हैं। तीव्र और अनियोजित शहरीकरण ने नगरों के प्रशासनिक ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। पेयजल संकट, ठोस कचरा प्रबंधन, बदहाल यातायात, प्रदूषण और मलिन बस्तियों का विस्तार आज हमारे जीवन की कड़वी सच्चाई बन चुके हैं। सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि आधुनिक शहरी प्रशासन एवं नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन की चुनौतियां 21 वीं सदी के ढाई दशक बीत जाने के बाद भी कम होने की जगह बढ़ती ही क्यों जा रही है? यह अब आवश्यक हो गया है कि हम अपनी शहरी प्रशासन प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करें और नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन को अधिक समावेशी, स्मार्ट और संधारणयोग्य (सस्टेनेबल) बनाएं।

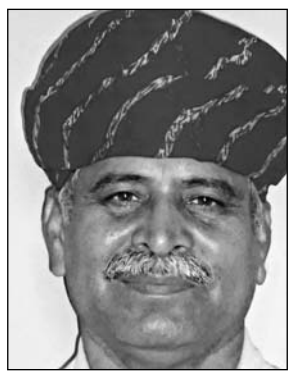
केवल तकनीक के भरोसे एक जीवंत शहर का निर्माण नहीं किया जा सकता। तकनीक एक साधन है, साध्य नहीं। जब तक बुनियादी ढांचे को ज़मीनी स्तर पर मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक डिजिटल स्क्रीन पर दिखने वाली स्मार्टनेस बेमानी साबित होगी। सफलता की असली कुंजीशहर के प्रशासन का दायित्वपूर्ण काम और व्यवहार में छुपी है। शहरी स्थानीय स्वशासन को वास्तविक अर्थ में लागू करना होगा। इसका अर्थ है कि नीति निर्धारण में आम जनता की आवाज़ सुनी जाए।

हमारा शहरी प्रशासन कई गंभीर संरचनात्मक और कार्यात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तीन चीजों की है: धन, कार्य और कर्मियों की कमी। नगर निकाय वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। वे राज्य और केंद्र सरकारों के अनुदानों पर निर्भर रहते हैं। संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली की व्यवस्था इतनी लचर है कि स्थानीय निकाय अपने प्रशासनिक खर्चे भी उनसे मुश्किल से निकाल पाते हैं। दूसरी समस्या कार्यप्रणाली में दोहराव की है। शहर के विकास के लिए विभिनं प्राधिकरण तथा विभाग अलग-अलग काम करते हैं। इन एजेंसियों के बीच समन्वय की भारी कमी होती है, जिसके कारण अक्सर एक ही सड़क को बार-बार खुदती दिखती है। इसके अलावा, नौकरशाही का अत्यधिक हस्तक्षेप तथा कुशल व तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों का अभाव शहरी निकायों को पंगु बना रहा है।

बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन में शहरी प्रशासन की सफलता की अंतिम कसौटी नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं होती हैं। यदि हम प्रमुख नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन पर नज़र डालें, तो स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। हर कहीं 24 घंटे पीने के पानी की आपूर्ति एक सपना बनी हुई है। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, और जल निकायों पर अवैध कब्ज़े हो चुके हैं। इसके साथ ही, अनुपचारित सीवेज का नदी-नालों में गिरना एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा है। हमारे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम या तो बहुत पुराना है या पूरी तरह अवरुद्ध है, जिसके कारण थोड़ी सी बारिश में ही शहर बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। शहरों से रोज़ाना हज़ारों टन कचरा निकलता है, लेकिन इसके वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था नाममात्र की है। शहरों के बाहर विशाल कचरे के पहाड़ वायु और भूमिगत जल को जहरीला बना रहे हैं। कचरे का स्रोत पर अलग-अलग न किया जाना इस संकट को और गंभीर बनाता है। गांवों से आजीविका की तलाश में शहर आने वाले गरीब अनियोजित कच्ची बस्तियों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। इन मलिन बस्तियों में सार्वजनिक सुविधाएं नहीं के बराबर मिलती हैं। यह स्थिति शहरों में सामाजिक और आर्थिक असमानता की खाई को और चौड़ा करती है। स्मार्ट सिटी मिशन और तकनीकी नवाचार जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटीज़ मिशन और अमृत जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ चुकी लगती हैं। उनसे नागरिक सुविधाओं को अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाने की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। केवल तकनीक के भरोसे एक जीवंत शहर का निर्माण नहीं किया जा सकता। तकनीक एक साधन है, साध्य नहीं। जब तक बुनियादी ढांचे को ज़मीनी स्तर पर मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक डिजिटल स्क्रीन पर दिखने वाली स्मार्टनेस बेमानी साबित होगी। सफलता की असली कुंजीशहर के प्रशासन का दायित्वपूर्ण काम और व्यवहार में छुपी है। शहरी स्थानीय स्वशासन को वास्तविक अर्थ में लागू करना होगा। इसका अर्थ है कि नीति निर्धारण में आम जनता की आवाज़ सुनी जाए। वार्ड समितियों और स्थानीय वेलफेयर संगठनों को बजट बनाने और प्राथमिकताओं को तय करने में शामिल किया जाए। मगर दुर्भाग्य से जन भागीदारी के नाम पर राजनीति का खेल ही चलता है। खुद नागरिकों में भी अपने शहर के प्रति जिम्मेदारी का भाव कहीं नज़र नहीं आता। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने शहरों को कंक्रीट के ऐसे बेजान जंगलों में बदलना जारी रखते हैं, या फिर उन्हें ऐसे रहने योग्य, सुरक्षित और समृद्ध केंद्रों के रूप में विकसित करते हैं जो मानव क्षमता को नई उड़ान दे सकें। आधुनिक शहरी प्रशासन को अब अपनी तदर्थ या संकटकालीन प्रबंधन की नीति को छोड़कर दीर्घकालिक, भविष्यवादी और संधारणीय नियोजन को अपनाना होगा। शहरी प्रबंधन में सुधार आज की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाले कल को सुरक्षित रखने की अनिवार्य शर्त है।हालत तभी सुधरेंगे जब हम अव्यवस्था को सामान्य मानना छोड़ देंगे, और यह मानना शुरू करेंगे कि हम इससे बेहतर के हकदार हैं।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

किसान हितों के संरक्षण के लिए बीज विधान तैयार करने की दिशा?



रामपाल जाट

सामान्यतया देश की खेती सामुदायिक बीज प्रणाली पर निर्भर है, जिसे अनौपचारिक बीज प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। यह करोड़ों किसानों के परिवारों की आजीविका तथा देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसलिए बीज संप्रभुता व्यापक जनहित का विषय है। बीज पर किसानों की संप्रभुता देशवासियों के सामान्य जीवनचर्या का अभिन्न अंग है। इसके विपरीत बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामुदायिक अनौपचारिक बीज प्रणाली को समाप्त कर औपचारिक बीज प्रणाली किसानों पर थोपने की दिशा में साम्राज्यवादियों के सहारे धनबल को आधार बनाकर कार्यरत हैं। वे बीज के व्यापार में एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं। इसी दिशा में वे प्रकृति एवं पर्यावरण को नष्ट कर 'जेनेटिकली मोडिफाइड' (जीएम) बीज के पक्ष में नितांत निराधार युक्तियां गढ़ती रहती हैं, उनके पक्ष में काम करने वाली 'लॉबी' भी सक्रिय रहती है। उनके पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह सर्वविदित होते हुए भी उनको छिपाने के असफल प्रयास करती रहती हैं। यथा- देश में जीएम के उत्पादों के आयात को रोकने के स्थान पर वे यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जब जीएम उत्पाद खाद्य तेल एवं अन्य पदार्थों के रूप में देश में आयातित हो रहे हैं तो उसी जीएम से देश में उत्पादन होने से तो देश को लाभ ही होगा। इसी प्रकार वे उच्च प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के रूप में जीएम का गुणगान करते रहते हैं। इसके विरोध करने वाले को आधुनिक प्रौद्योगिकी के विरोधी होने की संज्ञा देकर अपशब्द तक कहते हैं। इसी पद्धित में नपुंसक बीज जैसे प्रयोगों में होने वाली लूट से ध्यान हटाने के लिए उच्च मूल्य प्रणाली को शोध एवं अनुसंधान के खर्चों के लिए अपरिहार्य बताते हैं। ऐसे खर्चों को सरकार द्वारा वहन करने का आग्रह करने के विपरीत वे चुप्पी साधे रहते हैं।

सरसों का पायनियर कंपनी का बीज अधिकतम 1200 रुपया किलो, अन्य कंपनियों में सिंजेंटा, एडवांटा, बायर, कॉस्को, जेके सीडस, जैक्सन, इंडो यूस बायोटेक, अजीत आदि हैं, जिनके बीज का मूल्य 300 से लेकर 1200 रुपए प्रति किलो है। अर्थात एक क्विंटल सरसों का बीज बेचकर पायनियर कंपनी 1,20,000 रुपए वसूल करती है, जबकि इस एक क्विंटल सरसों के दाम उत्पादक किसानों को लगभग 8,000 रुपए प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम ने एक किलो सरसों बीज का मूल्य 115 से लेकर 200 रुपए निश्चित किया हुआ है। जिस एक क्विंटल बाजरे के बीज का दाम बीज कंपनियां 60,000 वसूलती हैं, उसी एक क्विंटल बाजरा का दाम उत्पादक किसानों को 2100 से 2,400 रुपए प्राप्त होते हैं। फल, सब्जी, मसाला के बीजों को बेचकर कंपनियां एक क्विंटल पर 90 लाख रुपए प्राप्त करती हैं। देश में चार दशक से कंपनियों के उत्पादों पर 'लागत मूल्य' अंकित करने की मांग की स्थिति अभी तक भी ढाक के तीन पात जैसी ही है। भारतीय संविधान में आय की समानता के लिए प्रावधान होते हुए भी आय की विषमता बढ़ाने के लिए यह भी प्रमुख कारक है। ब्रांडेड बीजों के लिए अधिकतम मूल्य निश्चित किए जाने के वैधानिक प्रावधान करने में सरकारों की विफलता विषमता की खाई को चौड़ा करने के लिए उत्तरदायी है।

देश में 70 से अधिक बीज गैर अधिसूचित श्रेणी में है। अनौपचारिक सामुदायिक बीज प्रणाली किसानों के हाथों में होने के कारण कुछ सीमा तक किसान बीज कंपनियों की लूट से बचे हुए है। फिर बीजों के लिए बीज कंपनियों पर निर्भरता कृषि उत्पादों में स्वावलंबन में बाधक है। पराधीनता इसी से जन्म लेती है।

तीसरी ओर बीज कंपनियां अपना ब्रांडेड बीज बेचने के लिए आकर्षक विज्ञापन के साथ लालच एवं डर का वातावरण तैयार करती है। कानूनी दांव पेंच में किसानों को उलझाकर वे अपने दुष्प्रयोजन को सफल बनाने में बेझिझक -बेशर्मी से व्यवहार करती है। 'राष्ट्रीय बीज निगम' द्वारा किसानों को लूट से बचाने की चुनौती स्वीकार कर इसे सही दिशा दी जा सकती है, इसमें सरकारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, अन्यथा छलावा द्वारा कंपनियों की लूट चलती रहेगी। इसी क्रम में आलू उत्पादक किसानों की व्यथा से सीख ली जा सकती है। जिसमें गुजरात के आलू उत्पादक किसानों को 8-9 वर्ष तक इसी प्रकार की व्यथा का दंश झेलना पड़ा।

सर्वोच्च न्यायालय ने बीज के संबंध में किसानों के अधिकारों की सुनिश्चितता व्यापक जनहित की रक्षा के लिए आवश्यक मानते हुए विधानों का मंतव्य स्पष्ट किया। इसके अनुसार देश के किसान बीज के उपयोग अथवा उपभोक्ता के रूप में प्रयोग के लिए पूर्णत स्वतंत्र हैं, वे अपनी पसंद के बीज बो सकते हैं, 'बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण' के किसी भी प्रकार के प्रावधान विद्यमान हो, उसका कोई भी स्त्रोत हो, किसानों को बीज बोने में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करता है। 'ब्रांडेड बीज' के अतिरिक्त सभी प्रकार के बीजों का उत्पादन, विक्रय, अंतरण का किसानों को अधिकार प्राप्त है। पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करने वाले पक्ष द्वारा दर्शाए अनुसार भारत की संसद में वर्ष 1999 में प्रस्तुत विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विभिन्न हित धारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत अनेक परिवर्तन किए जाने के सुझाव दिए, उसके बाद किसानों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करने के लिए किसानों के अधिकारों हेतु विधेयक में नया अध्याय सृजित किया गया। तब ही पौध प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को संसद ने विधान का स्वरूप प्रदान किया।

भारत सरकार द्वारा 'बीज अधिनियम 1966' एवं 'नियम 1968' के स्थान पर 'बीज विधेयक 2026' की तैयारी की श्रृंखला में देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिल्ली स्थित कृषि भवन में परिचर्चा का आयोजन किया गया। उससे बीज विधान चर्चा में आया। वर्ष 2025 में बीज विधेयक का प्रारूप तैयार हुआ, उसी का परिवर्धित स्वरूप 'बीज विधेयक 2026' है। जिसमें बीजों के पंजीकरण की अनिवार्यता का प्रावधान है, उसी अनुसार राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर पंजीकरण की व्यवस्था का उल्लेख है। यहां यह चर्चा भी प्रासंगिक है कि कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित विषय संविधान की राज्य सूची में वर्णित है, जिसके आधार पर इस संबंध में विधान निर्माण का दायित्व एवं अधिकार राज्यों का है। बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानो की वैधानिकता के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 18 अगस्त 2025 में बीज को समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 33 में सम्मिलित करने को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

प्रस्तावित बीज विधेयक 2026 के प्रयोजन में अधिसूचित प्रजातियों के बीजों की गुणवत्ता के लिए समुचित प्रणाली स्थापित कर बीजों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, बीजों के उत्पादन, वितरण, बिक्री की व्यवस्था को विनियमित करने, दंड के प्रावधानों को कठोर एवं प्रभावी बनाने, बीज क्षेत्र में निजी भागीदारी एवं आयात -निर्यात को सुविधाजनक बनाने, 70 गैर अधिसूचित श्रेणी के बीजों का विनियमन करने, बीजों के निष्फल होने पर किसानों को तात्कालिक अनुतोष देने, बीजों की पहचान में उत्तरदायित्व का निर्धारण करने जैसे विषयों का उल्लेख किया गया है। किसानों को प्रभावी एवं स्पष्ट संरक्षण देने की चर्चा के साथ आयात- निर्यात जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, नई प्रजातियों की गति को तेज करने, सभी राज्यों की प्रक्रियाओं में समानता लाने संबंधी प्रावधानों से उत्पन्न आशंकाओं के निवारण हेतु समुचित एवं अर्थपूर्ण भाषा की आवश्यकता है। अनेकों बार द्विअर्थी शब्दों, वाक्यांशों एवं वाक्यो से कंपनियों एवं वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करने वालों को लाभान्वित किया जाता रहा है। किसान हितों के नाम पर किसानों की लूट का खेल चलते रहने के कारण अविश्वास का वातावरण बना हुआ है, उसके खण्डन के लिए किसानों को विश्वास में लेने हेतु संसद /विधान मंडलों में विधेयक प्रस्तुति के बाद विधेयक को जनमत के लिए सौंपा जाना एवं राज्यों के विधान मंडलों को विधान निर्माण में सम्मिलित रखना श्रेयस्कर रह सकता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है इस लोकोक्ति को व्यवहार में उतारना सरकार का पवित्र धर्म है।

देशभक्त जागरूक किसानों को बीज विधान की सामान्य जानकारी तो रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके प्रभाव एवं परिणाम संबंधी अध्ययन के उपरांत चर्चा-विचार-विमर्श की निरंतरता किसान हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक सौपान हैं।

विधान निर्माण के साथ बीज ठाम की अवधारणा को बलवती बनाने हेतु पूर्व की भांति किसानों को अपनी आवश्यकता के लिए बीज उत्पादन करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। बीज कंपनियां भी धरती पर ही बीज का उत्पादन करती है। इस कार्य को तो हजारों वर्षों से अनुभव प्राप्त किसान अधिक सरलता से कर सकता है। शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता के लिए सरकारों द्वारा संकल्पयुक्त इच्छा शक्ति प्रकट करने की पहल देश की खाद्य सुरक्षा एवं किसानों की आजीविका के लिए सार्थक कदम सिद्ध होगा। इससे बीज क्षेत्र में कंपनियों की लूट से किसानो की रक्षा के साथ ही किसान हितों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।

रामपाल जाट-राष्ट्रीय
अध्यक्ष किसान महापंचायत

पुस्तक समीक्षा : चिड़ावा का गौरवशाली इतिहास



बाल मुकुन्द ओझा

राजस्थान के चिड़ावा, जिला झुंझुनूं के बहुमुखी प्रतिभा के धनि, साहित्यकार और समाजिक सांस्कृतिक चिंतक महेश कुमार शर्मा आजाद की गिनती देश और प्रदेश में अन्वेषी लेखक के रूप में की जाती है। आज़ाद 1980 से सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रीय है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक पत्रकार रहे है। आज़ाद की हाल ही में चिड़ावा का गौरवशाली इतिहास - ऐतिहासिक हवेलियां, कुएं, छतरी, शख्सियत और संस्थाएं 'प्रथम भाग' शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इससे पूर्व उनकी झुंझुनूं जिले की जुझारू महिलाएं, चिड़ावा के प्रमुख दर्शनीय मंदिर तथा राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर नामक तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है।

लेखक ने चिड़ावा को केवल एक कस्बे के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत के रूप में देखा है। चिड़ावा का गौरवशाली इतिहास पुस्तक का प्रथम भाग चार स्तंभों पर टिका है। हवेलियां: चिड़ावा की वो प्रसिद्ध हवेलियां जिनके भित्ति-चित्रों, नक्काशीदार दरवाजों और झरोखों में मारवाड़ी सेठों की समृद्धि और कला-प्रेम बसता है। लेखक ने इन हवेलियों के निर्माण काल, उनके मालिकों और उनकी वर्तमान स्थिति का प्रामाणिक विवरण दिया है। आवरण पर दिख रही नीले दरवाजे वाली हवेली इसी उपेक्षित सौंदर्य का प्रतीक है। कुएं और छतरियां: शेखावाटी के जल-प्रबंधन और स्मृति-स्थापत्य की पहचान रहे कुएं, बावड़ियां और छतरियां। ये केवल ईंट-पत्थर नहीं, बल्कि उस दौर के सामाजिक परोपकार और जल-संस्कृति की कहानी कहते हैं।

पुस्तक में इनके ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को उजागर किया गया है। शख्सियत और संस्थाएं: किसी भी नगर का इतिहास उसके लोगों से बनता है। लेखक ने चिड़ावा की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर व्यापार, शिक्षा और समाज सेवा में योगदान देने वाली विभूतियों और पुरानी संस्थाओं को भी सहेजा है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं। आज़ाद जी की भाषा सहज,



प्रवाहमयी और तथ्यपरक है।

उन्होंने यह इतिहास केवल किताबों से नहीं, बल्कि जमीन पर जाकर, बुजुर्गों से बात करके और खंडहर होती इमारतों को देखकर लिखा है। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी ताकत है। वास्तव में यह पुस्तक सांस्कृतिक एलबम है, जिसे आम पाठक भी रुचि से पढ़ सकता है। आज जब आधुनिकता की दौड़ में हमारी हवेलियां ढह रही हैं और कुएं भरते जा रहे हैं, ऐसे में यह पुस्तक एक चेतावनी भी है और एक दस्तावेज भी।

यह हमें याद दिलाती है कि विकास के साथ विरासत को बचाना कितना जरूरी है। चिड़ावा का गौरवशाली इतिहास केवल चिड़ावा के लोगों के लिए नहीं, बल्कि शेखावाटी, राजस्थान और स्थानीय इतिहास में रुचि रखने वाले हर पाठक, शोधार्थी और विद्यार्थी के लिए एक अनिवार्य पुस्तक है। पुस्तक 35 सचित्र अध्यायों से सज्जी है। लेखक महेश कुमार शर्मा आजाद बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने कस्बे के गौरव को शब्दों में अमर कर दिया।

समीक्षक कृति : चिड़ावा का गौरवशाली इतिहास।

लेखक : महेश कुमार शर्मा आजाद। समीक्षक - बाल मुकुन्द ओझा वरिष्ठ लेखक और पत्रकार

चाय पर संविधान

शाम का समय था। मौसम में उमस थी। मन में उससे थोड़ी ज़्यादा। सोचा, मोहल्ले में जाकर चाय पी जाए और किसी से अपने मन की बात की जाए।

मोहल्ले में पहुंचा तो मन खिन्न हो गया। वहां मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक हमारी नजर एक सज्जन पर पड़ी जो कि बार-बार हमें ही देखे जा रहे थे। चाय की चुस्की लेकर मैंने पूछा, आप कौन? पहचाना नहीं! उन्होंने आश्चर्य से हमे देखा और गंभीरता से कहा– मैं संविधान। मैं हंस पड़ा, आज के जमाने में इस तरह का नाम कौन रखता है? वह बोले सिर्फ नाम नहीं, मैं वास्तव में संविधान, इस देश का विधान हूँ। सोचा, आज संसद से निकलकर भारत यात्रा पर निकला जाए और जनता के बीच खुद को परखा जाए। पर यहां मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा हैं।

चाय वाला हमारी बात सुन रहा था। वह मेरी तरफ मुखातिब होकर बोला, बाबूजी, ये तो रोज का है कोई न कोई अपने को बड़ा आदमी बताता है और चाय मुफ्त में पीने की कोशिश करता है। परंतु मुझे लगा, यह जरूर कोर्ट कचहरी में उलझा व्यक्ति है जो अपने संवैधानिक हितों की बात कर रहा है।

फिर मैंने विनोद में कहा यदि आप वास्तव में संविधान है, तो प्रस्तावना सुनाइए। इतना सुनते ही उनके चेहरे पर तेज आ गया और कंठ में शंख सा उद्घोष हुआ वे बोले हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ईस्वी को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

अचानक चाय वाले ने जोरदार ताली बजाई, और कहा वाह। क्या संवाद है किसी अभिनेता की तरह। वे बोले, मैं विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान हूँ। मेरे पास न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है। तभी चाय वाला बोला साहब, किताब मोटी होने मात्र से बात गहरी हो जाती है क्या? संविधान थोड़ा सकपकाया। क्या मतलब?

चाय वाला बोला कहां पर है न्याय, देश में कितने लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं जिन्हें अपने मूलभूत अधिकारों तक का पता नहीं। तभी एक लड़का वहां से गुजरा। हाथ में एडमिट कार्ड था, कुछ हताश -परेशान सा। संविधान ने पूछा, बेटा, परीक्षा कैसी हुई। वो बोला– अंकल परीक्षा तो बाद में होगी, पेपर लीक हो गया। चाय वाले ने उबलती चाय की तरह संविधान को देखा। संविधान चुप हो गया। उसने जेब में हाथ डाला जेब खाली थी, दूसरी जेब टटोली, उसमें एक डिग्री निकली, उसने डिग्री लड़के को दे दी। डिग्री लेकर लड़का चाय वाले की दुकान पर ही बर्तन धोने लगा। मैंने संविधान की तरफ देखा। पहली बार वह गर्व से नहीं बोल रहा था। मैंने कहा संविधान बनता तो सदन में है पर लागू समाज पर होता है, जहाँ संविधान लोक नीति से ज्यादा वोट नीति हो वहां जनमानस की भावनाएं नेताओं के हाथों की कठपुतली बन जाती है। संविधान धीरे से बोला, मैं दोषी नहीं हूँ। लेकिन मेरे नाम पर जो हो रहा है, उससे भी अनजान नहीं रह सकता। संविधान और कुछ कहता तभी चाय वाला बोला–साहब बुरा मत मानना, संविधान और चाय तब तक ही अच्छी लगती है जब उसकी प्रक्रिया सही हाथों में हो, बंदर के हाथ में उस्तरा आता है तो वह दाढ़ी नहीं बनाता है।

इतने में बूंदाबांदी शुरू हो जाती है संविधान कहता है जनता ही असली लोकतंत्र और संविधान है, जनता का दिया सही मतदान ही सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है।

संविधान की बात सुनकर चाय वाले ने चाय आगे बढ़ाते हुए कहा उमस होगी तो बरसात होगी, बरसात होगी तो चाय होगी, चाय होगी तो बात होगी, बात होगी तो निश्चित उजाले की राह होगी। और संविधान भी कभी दरकते कुल्हड़ में से गिरती अपनी चाय को तो कभी चाय वाले के झोपड़ी में से गिरती बूँदों को देखे जा रहा था। और मैं सोच रहा था यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, इस देश की आत्मा का सम्मानित विधान है।

–मनोज गोयल,
स्वतंत्र टिप्पणीकार

राशिफल



पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 4 नवम्बर, 2026

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत–2083, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 3:30 तक, ब्रहम योग प्रात: 8:01 तक, विष्टि करण दिन 11:04 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-तुला, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरू-सिंह, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज भद्रा दिन 11:04 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:26 तक, शुभ 10:18 से 12:10 तक, चर 2:54 से 4:16 तक, लाभ 4:16 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल– 12:00 से 1:30 तक, सूर्योदय 6:42, सूर्यास्त 5:38

मेष

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। परिवार में वाद-विवाद एवं स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

वृष

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।

मिथुन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। शुभ-धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्